

प्रदेश के नौ धार्मिक स्थलों का किया जाएगा पर्यटन विकास

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : प्रदेश के नौ धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की स्वीकृति शासन ने दी है। उन्नाव, सिद्धार्थनगर, झांसी, चंदौली, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात व कुशीनगर में स्थित इन धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत किया जाएगा। योजना के तहत संबंधित पर्यटन स्थल के विकास पर 50 प्रतिशत राशि सरकार की तरफ से और 50 प्रतिशत की राशि प्रस्तावक की तरफ से खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक पर्यटन स्थल की सूची तैयार की जा रही है। शासन ने जिन धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की स्वीकृति दी है उनमें उन्नाव के टेढ़ा ग्रामसभा में स्थित शिखरेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धार्थनगर के बांसी में स्थित बागेश्वरी मंदिर व यहीं के दुमरियागंज में स्थित तीरथ सागर भारत भारी मंदिर, झांसी के सीपरी में स्थित लहरकी देवी व मोटी कटरा स्थित बलुवा घाट मंदिर, चंदौली के सिद्धार्थपुरम में स्थित शालिग्राम नाथ मंदिर, कानपुर देहात के भोगनीपुर में स्थित मुक्तादेवी मंदिर, अंबेडकर नगर के आलापुर में स्थित राम जानकी मंदिर व कुशीनगर के फाजिलनगर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर के नाम शामिल

- प्रयागराज में निर्मित किया जाएगा भजन संध्या स्थल
- शासन ने दी स्वीकृति, 75-75 हजार रुपये की राशि जारी

इन जिलों में होगा विकास

अंबेडकर नगर के आलापुर में राम जानकी मंदिर, उन्नाव के टेढ़ा ग्रामसभा में स्थित शिखरेश्वर महादेव मंदिर, कुशीनगर के फाजिलनगर में दिगंबर जैन मंदिर, झांसी के सीपरी में स्थित लहरकी देवी व मोटी कटरा स्थित बलुवा घाट मंदिर, सिद्धार्थनगर के बांसी में स्थित बागेश्वरी मंदिर व यहीं के दुमरियागंज में स्थित तीरथ सागर भारत भारी मंदिर, चंदौली के सिद्धार्थपुरम में स्थित शालिग्राम नाथ मंदिर, कानपुर देहात के भोगनीपुर में मुक्तादेवी मंदिर।

हैं। इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रथम किस्त के रूप में 75-75 हजार रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 11.44 करोड़ रुपये की राशि भी शासन ने जारी की है।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास कराने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। योजना के तहत सांसद व विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित पर्यटन स्थलों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।